

State	No. of Estates completed during III Five Year Plan so far.
Madhya Pradesh	9
Mysore	6
Orissa	6
Pondicherry	1
Punjab	33
Tripura	1
Rajasthan	9
Uttar Pradesh.	43
West Bengal	1
	109
Total 60 + 109 = 169	

(b) The types of incentives generally given for setting up Industrial units in Industrial Estates are the following:

(1) Built-in sheds are made available on rental basis or on hire purchase terms,

(2) Subsidized rent is charged for 5 years,

(3) common service facilities like tool rooms are provided in the vicinity of Industrial Estates.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

N.C.D.C. Coal Mines

982. { Shri Kanakasabai:
Shri Mohammed Koya:

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three coal mines under the National Coal Development Corporation have suspended production while in three other mines work has been slowed down;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the loss of production sustained in this process?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (c). To prevent a continued imbalance between the production of coal and its offtake, the National Coal Development Corporation has suspended production in four of its mines and slowed it down in seven other mines. As production is being matched with the demand for coal, and is increased as the demand picks up, there is no question of sustaining any loss of production.

Export of Silk Fabrics

983. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian silk fabrics are becoming more popular in foreign countries;

(b) whether there has been any increase in the export of these fabrics during the last two years; and

(c) whether Government have under consideration any export promotion scheme for these fabrics to earn more foreign exchange?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) Yes. The value of exports during the last two years was as follows:—

Year	Value
	(Rs. in lakhs)
1963	216.12
1964	222.96

(c) A comprehensive Export Promotion Scheme for Natural Silk Fabrics has been in operation since 1st January, 1958.

Export of Textiles to U.K.

984. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the agreement regarding the export of

Indian cotton textiles to Britain will expire in 1965;

(b) what was the duration of this agreement and whether Government are considering to extend the same: and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The duration of the present agreement is three years, i.e., from 1963 to 1965. What arrangements should be made for the export of cotton textiles to the U.K. for 1966 onwards is engaging the attention of the Government of India and the U.K. Government.

टीन की चादरों से भरे माल डिब्बों का कब्जे में लेना

985. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1965 के प्रथम सप्ताह में कानपुर (उत्तर प्रदेश) के जिला अधिकारियों ने वहाँ रेलवे यार्ड से टीन की चादरों से भरे हुए लगभग आधे दर्जन माल डिब्बे कब्जे में ले लिए, जो शीघ्र ही पाकिस्तान भेजे जाने वाले थे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन 7-7-1965 को कानपुर के एक फार्वर्डिंग एजेंट ने कूपरगंज से नरोड़ा के लिए दो परेषण बुक किये थे, जिनमें लोहे की जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों के क्रमशः 50 और 52 बण्डल थे। जिलाधीश के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने कूपरगंज में माल कब्जे में ले लिया क्योंकि पुलिस को इस बात का सन्देह था कि हो सकता है यह

माल नरोड़ा में चोर बाजार में बेचा जाय और उसके बाद चोरी-छिपे पाकिस्तान को भेजा जाय। पुलिस ने 3/7 बी० सी०/ भारत रक्षा नियम की धारा 125 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उत्तर प्रदेश का खुफिया पुलिस विभाग इस की जांच-पड़ताल कर रहा है।

रेलवे इलेक्ट्रिक वर्कशाप दिल्ली से रेफ्रिजरेटरों की चोरी

986. श्री हुकम चन्द पट्टनायक : क्या रेलवे मंत्री 9 अप्रैल, 1965 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2138 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय के विशेष पुलिस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वर्कशाप, दिल्ली से चुराये गये रेफ्रिजरेटरों सम्बन्धी जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) प्रशीतन और वातानुकूलन उपस्कर में इस्तेमाल के लिए विदेशों से मंगाये गये तथा देश में तयार किये गये कीमती फालतू पुर्जों के अनुरक्षण और निबटारे में दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के वातानुकूलन कारखाने में जो अनियमितताएं हुई हैं उनके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय की विशेष पुलिस सिब्बन्दी ने अब जांच पूरी कर ली है।

(ख) और (ग). विशेष पुलिस सिब्बन्दी की अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और रिपोर्ट मिल जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।